बीके अस्पताल के डॉक्टरों का कमीशन खाने का नायाब तरीका

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा सरकार ने ग़रीब मरीज़ों को दवा कम्पनियों की लूट से बचाने के लिये आधे-अधूरे मन से फ़र्मान जारी कर रखा है कि मरीजों को दवायें सरकारी अस्पतालों से ही मुफ़्त मिलेगी और यदि बाहर से खरीदने के लिये डॉक्टर को लिखनी भी पड़े तो वह महंगे ब्रांड नाम की दवायें न लिख कर जेनरिक नाम ही लिखेंगे।

लेकिन स्थानीय बादशाह खान अस्पताल के दो डॉक्टरों-दारा सिंह राठी व सुभाष गुप्ता ने सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का बड़ा ही नायाब तरीका खोज निकाला है। दोनों ही कलाकार त्वचा रोग विशेषज्ञ बताये जाते हैं। ये मरीज़ को देखने के बाद अपने तरीके से समझाते हुए उसी मरीज़ या उसके तीमारदार के हाथ से एक पर्ची पर दवा का नाम लिखवाते हैं ताकि पकड़े जाने पर साफ़ मना कर सकें कि उन्होंने कोई दवाई लिखी थी।

इस तरह की लिखी हुई दवा जिस कैमिस्ट के यहां मिलेगी उसका पता भी ये साहेबान बता देते हैं। शाम तक या अगले दिन तक कैमिस्ट इस तरह बेची गयी दवाओं का हिसाब यानी तय कमीशन आराम से दे जाता है। लेकिन जब कैमिस्ट ने हेरा-फ़ेरी करते हुये हिसाब में गड़बड़ी शुरू की और कहने लगा कि मरीज तो दवा लेने आया ही नहीं तो इन कलाकारों ने इसका भी तोड़ निकाल छोड़ा।

अब ये डॉक्टर अपने मरीज़ से कहने लगे कि दवा खरीद कर उन्हें दिखा कर भी जाओ। मरीज़ बेचारे दिखाने लगे तो कैमिस्ट ने कहना शुरू कर दिया कि कुछ मरीज़ तो खरीदने के बाद वापस कर गये।

डा. सुभाष गुप्ता

लेकिन ये दोनों डॉक्टर कौन से कम थे, ये भी पहुंचे हुये कलाकार निकले। इन्होंने मरीज़ द्वारा लाई गयी क्रीम की ट्यूब को खोल कर, कुछ क्रीम निकाल कर उसे लगाने का तरीका बताना शुरू कर दिया। इस प्रकार खुली हुई ट्यूब तो वापस हो नहीं सकती, लिहाजा कैमिस्ट की हेरा-फेरी का रास्ता बन्द हो गया। इतना ही नहीं, इस नायाब तरीके को इस्तेमाल में लाने के बाद इन डॉक्टरों ने एक कैमिस्ट पर निर्भरता छोड़ कर कैमिस्टों की संख्या भी बढा ली है।

आवारा कुत्तों के बचाव में उतरे मेनका गांधी के एजेंट

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो लखनऊ

गतांकों में सुधी पाठकों ने पढा होगा कि यूपी के सीतापुर ज़िले में किस तरह एक गांव के 15 बच्चों को आवारा कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिया था। सरकार को लगाई गुहार का जब कोई परिणाम नहीं निकला तो गांव वालों ने मिल कर लाठियों से उन कुत्तों को मार डाला था।

मासूम बच्चों के कुत्तों द्वारा मारे जाने पर चुप रहने वाले मेनका गांधी के एजेंट कुत्तों के मारे जाने पर बिलबिला उठे। उन्होंने पहले दिल्ली व लखनऊ में बयानबाज़ी करते हुए कुत्तों की मौत पर आंसू बहाये और बाद में सरकार तथा अदालत में गुहार लगाई कि इस बात की जांच कराई जाय कि जिन कुत्तों को मारा गया है क्या उन्हीं कुत्तों ने बच्चों को खाया था? यदि जांच में पाया जाय कि बेगुनाह कुत्तों को मारा गया है तो उन ग्रामीणों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय जिन्होंने 'बेगुनाह' कुत्तों को मारा है।

विदित है कि भारत में आवारा घूमने वाले कुत्तों की कुल संख्या ढाई करोड़ के करीब है। देश में रैबीज़ रोग के ये कुत्ते सबसे बड़े संवाहक हैं। विकसित देशों ने अपने यहां से तमाम आवारा कुत्तों को समाप्त करके अपने आप को रैबीज से पूर्णतया मुक्त कर लिया है। जबकि भारत में इस रोग से, इलाज के अभाव में हर साल हज़ारों लोग मर जाते हैं। किसी भी बड़े शहर में हर साल 20-30 हज़ार कुत्ता काटे के मरीज़ अस्पतालों में आते हैं। 100 रुपये में लगने वाला सरकारी टीका जो अक्सर उपलब्ध नहीं होता तो बाज़ार से 400-600 रुपये के लगवाने पड़ते हैं।

इस हिसाब से रैबीज इन्जेक्शन बनाने वाली कम्पनियों के लिये भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है। इस बाज़ार को बनाये रखने एवं फलता-फूलता रखने के लिये टीका निर्माता कम्पनियों को मेनका गांधी जैसे कुत्ता प्रेमियों की बहुत अधिक आवश्यकता है। अपनी इस आवश्यकता पूर्ति के बदले यदि वे मेनका के एनजीओ को जम कर चंदा आदि दे रहे हों तो क्या हर्ज है।

दिल्ली विश्वविद्यालय- फीस का अर्थशास्त्र

रवींद्र गोयल की विशेष रपट

एक ही विश्वविद्यालय में एक ही पढ़ाई पढने के लिए फीस अलग अलग है। सबसे कम फीस 3046 रुपये सालाना है तो अधिकतम फीस 38105 रुपये सालाना है। बाकी कॉलेज इन दो सीमाओं के भीतर फीस वसूलते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में इस साल 66 संस्थाओं में बीए स्तर पर दाखिले किये जायेंगे। (दो विश्वविद्यालय विभाग और 64 कॉलेज)। जानकारी हो की यह विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यहाँ देश का कोई भी छात्र बिना भेदभाव के दाखिला ले सकता है (बेशक आजकल निहित स्वार्थों द्वारा इसके केंद्रीय चरित्र पर सवाल उठाये जा रहे हैं, पर वो कहानी फिर कभी) इस समय यह विश्वविद्यालय देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में माना जाता है और हर वो छात्र जो यहाँ पढाई का खर्चा दे सकता है और दाखिला पा जाता है वो यहाँ पढ़ सकता है। लेकिन वो पढ़ पायेगा की नहीं वो इस बात पर भी निर्भर करेगा की दाखिले की पात्रता के अलावा उसके पास फीस आदि देने की हैसियत भी है या नहीं।

स्तरीय पढ़ाई केवल पढ़ने वाले के लिए ही गरीबी से मुक्ति की राह नहीं खोलती बल्कि व्यापक समाज के लिए भी हितकारी है इसीलिए आज के दौर में यह सभी जिम्मेवार व्यक्तियों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है की राज्य द्वारा सब युवाओं के लिए सस्ती शिक्षा की सुविधाएँ मुहैय्या कराई जानी चाहिए। पिछले कुछ सालों में इस सोच पर हुक्मरानों ने पलटी मारी है। तर्क है कि सरकारों को और जरूरी काम करने चाहिए और शिक्षा को गैर सरकारी हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए। निजी स्वार्थी तत्व भी इस तर्क से संभावित मुनाफे के मद्देनजर शिक्षा के निजीकरण के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे रहते हैं।

लेकिन पहले की बनायीं हुई संस्थाओं को रातों रात खत्म कर देना संभव नहीं है। ऐसी ही संस्था है दिल्ली विश्वविद्यालय। यहाँ कानूनी तौर पर बहुत कम खर्चे में पढाई की जा सकती है। बीए की पढाई के लिए ट्यूशन फीस है मात्र 15 रुपये महीना या 180 रुपये सालाना और शेष सभी खर्चा भारत सरकार देने के लिए बाध्य है। बेशक यहाँ भी अपनी जिम्मेवारियों से हटने के लिए सरकार ने पिछले बीस/ पच्चीस सालों से कोई कॉलेज नहीं खोले हैं पर अब तक ट्यूशन फीस नहीं बढ़ा पाई है। ऐसी स्थिति में और चारों तरफ निजीकरण के बढ़ते शोर में यूनिवर्सिटी अफसर, प्रिंसिपल्स और शिक्षकों के एक हिस्से ने फीस बढ़ोतरी के माध्यम से भ्रष्टाचार और हेराफेरी का एक चोर दरवाजा ढूंढ लिया है। आलम यह है एक ही विश्वविद्यालय में एक ही पढाई पढने के लिए फीस अलग-अलग है और कितना अंतर है इसका अंदाजा निम्न से लगाया जा सकता है। सबसे कम फीस 3046 रुपये सालाना है तो अधिकतम फीस 38105 रुपये सालाना है। बाकि कॉलेज इन दो सीमाओं के भीतर फीस वसूलते हैं।

संस्था का नाम	सालाना फीस 2018-19 के लिए
डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज	3046 रुपये
सैंट स्टीफेंस कॉलेज	38105 रुपये

स्रोत- एडमिशन बुलेटिन 2018- 19

तय है की यह राशि छात्रों से विभिन्न मदों में वसूली जाती है। और कितने गैर जरूरी / मनमाने होंगे ये मद इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि JNU में सालाना फीस आज भी केवल 400 रुपये ही है। यदि वहां फीस इतनी कम है और DU में मनमानी फीस तो इसका एक मात्र कारण है की जहाँ JNU के छात्र और शिक्षक फीस के सवाल के महत्व को समझते हैं वहीं इस सवाल पर DU में शिक्षकों/ छात्रों की कोई चिंता नहीं है। मध्यम वर्ग से आने वाले ये तत्व आम समाज से कितना कटे हुए हैं इसका यह सबूत है। उम्मीद करनी चाहिए की प्रगतिशील छात्र/ शिक्षक/कर्मचारी इस सवाल के महत्व को समझेंगे और इस सवाल को मुस्तैदी से उठाएंगे और मांग करेंगे की DU में मनमानी फीस का चलन बंद हो नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब मजदूर किसान और मेहनतकश तबकों के बच्चे विश्वविद्यालय की शिक्षा से बिलकुल बाहर खदेड़ दिए जायेंगे। ध्यान रहे की सरकार ने उच्चशिक्षा का 30 फीसदी खर्चा छात्र फीस से वसूल करने की अपनी मंशा का इजहार कर दिया है। पंजाब विश्वविद्यालय में इसको लागू करने की कोशिश भी कुछ दिन पहले हो चुकी है। ये अलग बात है की वहां के छात्रों के प्रबल विरोध के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा था।

योगी सरकार दलितों-मुसलमानों पर रासुका लगाकर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताने पर आमादा

लखनऊ (म. मो.) बहराइच के नानपारा में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निरुद्ध किए गए लोगों के परिजनों से रिहाई मंच प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में सृजनयोगी आदियोग, लक्ष्मण प्रसाद, वीरेन्द्र गुप्ता, नागेन्द्र यादव, राजीव यादव के साथ बहराइच से वरिष्ठ पत्रकार सलीम सिद्दीकी और नूर आलम शामिल थे।

प्रतिनिधि मंडल ने रासुका के तहत निरुद्ध किए गए मुन्ना, नूर हसन, असलम, मसहूद रजा, मो0 अरशद के परिजनों व ग्राम वासियों से मुलाकात की। 2 दिसंबर को बारावफात के जुलूस के दिन सांप्रदायिक तनाव होने के बाद बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की गिरफ्तारियां हुईं। जिसमें निचली अदालत से बहुत कम राहत मिली और हाईकोर्ट से लोगों को जमानत मिली। इस मामले में 5 व्यक्तियों पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई।

मुन्ना के भाई अब्दुल खालिद ने बताया कि वह उस दिन ईट भट्टे से मजदूरी करके लौटा था कि पुलिस वाले आ धमके और उसके साथ दो भतीजों साजन, राजन और भाई नसीबुल को उठा ले गए। बाद में मुन्ना पर रासुका लगा दिया गया।

रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालने वाले नूर हसन की पत्नी अकीला बानो दो साल की बेटी सैयदा को दिखाते हुए बताती हैं कि ये बीमार थी। इसकी दवा लेने के लिए वो डा0 हुसैन बख्श के यहां गए थे पर बवाल की वजह से दवा नहीं मिली। तभी पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने उनको बैठा लिया। हमने पूछा तो कहा कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं. तब से वो नहीं आए। यह पूछने पर कि क्यों नहीं वो छूट रहे हैं तो वह बोलती हैं कि वो नहीं जानती। वो तो इस बात से ही परेशान हैं कि जेल में मिलाई का ही उनके पास पैसा नहीं है वो क्या केस लड़ेगी। उनके पति के ऊपर रासुका लगी है ये तो वो जानती हैं पर ये है क्या वो नहीं जानती।

असलम की पत्नी शग्तो बताती हैं कि उस दिन वो अपनी चूडियों की दुकान पर थे वहीं से पुलिस ने उन्हें उठाया और अब तक नहीं छोड़ा। हफ्ते में तीन मिलाई होती हैं पर मुष्किल से वो एक या दो बार महीने में जा पाती हैं क्योंकि एक बार जाने में ही डेढ़-दो सौ रुपए लग जाते हैं। रासुका को वह बार-बार असोका कहती हैं और पूछने पर नहीं बता पाती हैं कि क्या है ये। बस यही जानती हैं कि यह कोई बड़ी धारा है जिसको सरकार लगाती है।

मदरसे में पढ़ाकर अपने परिवार को पालने वाले मसहूद रजा के पिता खलील बताते हैं कि वह उस दिन अपनी बहन से मिलने गया था और बाजार में जैसे ही बच्चों के खाने-पीने की चीजें खरीदकर घर आ रहा था कि पुलिस ने उसे उठा लिया। उसका आधार कार्ड, मोबाइल सब जब्त कर लिया। उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। वो कहते हैं कि मैं चल फिर पाने में लाचार हूं ऐसे में मैं खुद का तो कुछ नहीं कर पाता उसके परिवार का कैसे पालन-पोषण करुं।

अरशद की मां शमा बताती हैं कि वो एक दिन पहले केरल से आया था. वह वहीं पढ़ता था और यह उसका आखिरी साल था। पर पुलिस ने उसे ऐसा फंसाया कि उसका कैरियर ही बर्बाद हो गया। मेरे 19 साल के बेटे पर रासुका लगा दी गई हैं। वहीं अरशद की बहन कनीज फातिमा भी अपने भाई और खासतौर पर उसकी पढ़ाई को लेकर फिक्रमंद हैं। रासुका पर वो कहती हैं कि यह देशद्रोह जैसा है। वो सवाल करती हैं कि आखिर उनके भाई ने ऐसा क्या किया था कि उन पर रासुका थोप दिया गया। अरशद की अम्मी बताती हैं कि उनके पति शाहिद के साथ त्योहार पर मिलने आए भाई अब्दुल मुहीद, बहनोई खालिद व उनके साथ आए 14 साल के कलीम को भी पुलिस उठा ले गई।

रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने कहा कि योगी सरकार दलितों व मुसलमानों पर रासुका लगाकर पूरे समाज को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक घोषित करने का षडयंत्र रच रही है। इसी के तहत उसने भीम आर्मी के संस्थापक चन्द्रशेखर पर रासुका लगाया और अब भारत बंद के नेताओं पर भी लगातार लगा रही है। रिहाई मंच ने इस मनुवादी और सांप्रदायिक षडयंत्र के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बहराइच के नानपारा का दौरा किया। उन्होंने बताया कि इसके तहत बाराबंकी, कानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि का दौरा किया जाना है जहां रासुका के तहत दलितों-मुसलमानों को निरुद्ध किया गया।

कॉलेज बने नहीं, स्टाफ़ लगा नहीं, दाखिले शुरू

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते 4 साल में कोई भी काम करने में असफ़ल रही भाजपा सरकार को जब चुनाव सिर पर नज़र आने लगे तो झटपट दो महिला कॉलेजों की न केवल घोषणा कर दी बल्कि 6 जून से इनमें दाखिला प्रक्रिया शुरू करने की भी घोषणा कर डाली।

इनमें से एक कॉलेज बल्लबगढ के सेक्टर 2 में तथा दूसरा नचोली गांव में बताया जा रहा है। ये दोनों महिला कॉलेज बल्लबगढ विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहां से विधायक मूलचंद शर्मा राज्य के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के बहुत निकट सम्बन्धी हैं। शायद इसी लिये मूलचंद के खाते में एक साथ दो कॉलेज डाल कर उनका क्रेडिट स्कोर बढाने का प्रयास किया गया है।

अब जानने योग्य बात यह है कि उक्त दोनों कॉलेजों की इमारत अभी निर्माणाधीन है जिसे पूरा होने से पहले लोकसभा चुनाव आ सकते हैं। इसके बावजूद इन कॉलेजों के लिये दाखिला प्रक्रिया चालू होने जा रही है। इसके लिये आस-पास के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दुरुपयोग करने की योजना है। सर्वविदित है कि इन स्कूलों सहित सभी सरकारी स्कूलों की इमारतें अपर्याप्त एवं खस्ता हाल हैं। इन में पहले से दाखिल अपने छात्रों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनमें अब खट्टर सरकार महिला कॉलेज चलाने का ड्रामा करेगी।

चलो, ड्रामे के लिये स्थान तो ढूंढ ही लिया, परन्तु दाखिला लेने वाली लड़कियों को पढायेगा कौन? मजे की एक बात यह भी है कि इन कॉलेजों में साइंस पढाने का भी दावा किया जा रहा है जबकि इसके लिये आवश्यक प्रयोगशालाओं का कोई अता-पता नहीं।

सेक्टर 2 वाले कॉलेज का प्रधानाचार्य पद अतिरिक्त रूप से तिगांव की प्रधानाचार्य सुमन को, तो नचोली कॉलेज का अतिरिक्त प्रभार सेक्टर 16 ए फ़रीदाबाद के महिला कॉलेज की प्रधानाचार्य भगवती राजपूत को सौंपा गया है। यह बड़ा ही हास्यास्पद है। ये दोनों महिलायें अपने नियमित कॉलेज को छोड़ कर भला नये तथाकथित कॉलेजों में क्यों जाने लगी? सरकार ने इनके आने जाने का कोई प्रबन्ध भी नहीं किया है; फ़िर यदि ये वहां चली भी गयी तो करेंगी क्या? वहां करने-धरने को है भी क्या? रही बात पढाने वाले स्टाफ़ की, तो जानकारों के अनुसार प्रधानाचार्यों की तरह प्राफ़ेसरों को भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जायेगा। वे 3 दिन इस कॉलेज में तो 3 दिन दूसरे कॉलेज में 'पढायेंगे' जिसका वास्तविक परिणाम यह होगा कि पढाई न यहां होगी न वहां जबकि पढाने का ड्रामा दोनों जगह चलता रहेगा।

जनता इतनी बेवकूफ़ भी नहीं रह गयी है जो इस सियासी ड्रामे को समझ न सके वह इस सारे खेल को समझ रही है और समय आने पर जवाब भी देगी।